

असाधाररा EXTRAORDINAR)

भाग II—इंग्ड 3—उप-क्षण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं, 105] निर्देशना विस्ति, बुधवार, मार्च 1, 1989/फाल्गुन 10 1910 No. 105] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1. 1989/PHALGUNA 10, 1910

इस भाग में भिम्न पूछ्ट संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संवासन को रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

प्रदेश

मर्च विरुर्ला, 1 मार्च, 1959

वा था. 168 (भ):--फेर्न्झीय सरकार ने 1 मार्च, 1989 से सीमेट के मूल्य और विसरण नियन्नण को हटाने का विनिध्सय किया है ; श्रव, मतः, केन्द्रीय सरकार उद्योग (जिकास और विभियमन) श्रिधियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ग और धारा 25 हारा प्रदेस मिन्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमेट नियमण श्रावेण, 1967 में निम्न- लिखित संशोधन करती है, सर्थातः-

- 1. (1) इस भावेश का संक्षिप्त नाम सीमेट नियंत्रण (संशोधन) ग्रादेश, 1989 है ।
- (2) यह 1 मार्च, 1989 को प्रश्रस होगा।
- 2. सीमेंट नियंत्रण मादेश, 1967 की प्रस्तावना के पैरा 1, पैरा 1क, पैरा 2 के खण्ड (घ) और (ग) पैरा 3, 3क, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 12 और उसकी भन्भूनी का लोग किया जाएगा :

परन्तु ऐसे लीप किए जाने से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा---

- (क) उक्त पैराओं का पूर्व प्रवर्तन या उसके प्रधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई काई बात
- (आ) उन्त पैराओं के प्रधीन उद्भूत, प्रजित या उपगत कोई श्राधिकर, विशेषाधिकार, बाध्यसा या वायित्व; या
- (ग) उक्त पैराओं के संबंध में किए गए श्रपराध की याबत उपगत कीई शास्ति, समपहरण या वण्ड; या
- (य) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी प्रधिकार, थिशेषाधिकार, बाध्यता, वायित्व, शास्ति, समपहरण या धण्ड की वाबत कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, और
- (क.) ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित की जा सकेगी, चलाई आ सकेगी या प्रवर्तित की जा सकेगी और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त पैराओं का लोप न विधा गया हो।

सि. 1-5/89——गोभेल्ट] ग्रार.के. सिल्हा, संयुक्त सचिव

टिज्पण :--- (मूल भावेश का. भा. 4590/18जी/67 तारीख 23-12-1067 द्वारा ग्रधिसूचित किया गया था)।

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 1st March, 1989

S.O. 168(E).—Whereas the Central Government has decided for the removal of price and distribution control of cement with effect from the first day of March, 1989;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 18G and 25 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the

Central Government hereby makes the following amendment in the Cement Control Order, 1967, namely:—

- 1. (1) This Order may be called the Cement Control (Amendment) Order, 1989;
 - (2) It shall come into force on the First day of March, 1989.
- 2. Paragraph 1 to the Preamble, Paragraph 1A, clauses (d) and (e) of paragraph 2, paragraph 3, 3A, 4, 5, 7, 8, 9, 10 and 12 and Schedule to the Cement Control Order, 1987, shall be omitted:

Provided that such deletion shall not affect -

- (a) the previous operation of the said paragraphs or anything duly done or suffered thereunder;
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said paragraphs; or
- (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said paragraphs; or
- id) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, and
- (e) any such investigation, legal proceeding or remedy may be institated, continued, or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said paragraph had not been omitted.

[No. 1-5]89-Cem.] R. K. SINHA, Jt. Secy.

Note: The principal order was notified vide S.O. 4590-IDRA 18G 67. dt. 23rd December, 1967.